के अनुसार राज्यवार कोयले के भंडारों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

(आवर्ती भण्डार मि० टन में)

राज्य	1–1–90 की स्थिति के अनुसार	1–1–91 की स्थिति के अनुसार
आंध्र प्रदेश	10596.64	10771.35
अरूणांचल प्रदेश	90.23	90.23
असम	292.68	295.18
बिहार	61155.11	62084.85
मध्य प्रदेश	32649.93	37053.18
महाराष्ट्र	5553.15	6071.18
मेघालय	458.94	459.43
नागालैंड	19.94	19.94
उड़ीसा	44261.54	44304.43
उत्तर प्रदेश	1062.21	1062.21
पश्चिम बंगाल	29903.87	30147.17
जोड़	1,86,044.24	1,92,359.15

गुजरात तेल शोधक कारखाने कार्यकरण

*213. **डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 अप्रैल, 1991 के "दि टाइम्स आफ इंडिया" में "आई०ओ०सी० डिनाइज ओ०एन०जी० सी० चार्ज आफ स्लोइंग डाऊन प्रोडक्शन" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के प्रबंधन ने इस आशय का एक स्पष्टीकरण दिया है कि पिछले वर्ष कच्चे तेल के उत्पादन में इसलिये कमी की गई थी क्योंकि गुजरात तेल शोधक कारखाने में तेल-शोधन प्रक्रिया की पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण वहां से कच्चे तेल का उठान नहीं हो रहा था ;

(ग) यदि हां, तो क्या यह सच है कि पिछले वर्ष के दौरान गुजरात तेल शोधक कारखाने में तेल शोधन का कार्य बड़े पैमाने पर किया गया था और उत्पादन का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के स्पष्टीकरण की ओर जांच की है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री वी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) यद्यपि गुजरात रिफाइनरी ने 1990–91 में अपने अधिकतम उत्पादन का लक्ष्य पूरा कर लिया है फिर

भी कुछ ऐसे महीने भी थे जिनमें तकनीकी/प्रचालनगत कारणों से संसाधन में कुछ कमी आई थी।

तेल के क्षेत्र में निवेश

*214. श्री राम अवधेश सिंह।
श्री गुफरान आजम।

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री 15 जुलाई, 1991 को राज्य सभा में तारांकित प्रश्न संख्या 23 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल के क्षेत्र में पूंजी निवेश करने के लिए विदेशों में रह रहे भारतीयों को आमंत्रित किया है, जैसा कि दिनांक 3 जुलाई, 1991 के "दि बिजनेस एण्ड पालिटिकल आब्जरवर" में प्रकाशित हुआ है, यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ख) गैस और तेल निकालने के कार्य में लगी हुई अंतरा-ट्रीय और स्वदेशी कंपनियों की अलग-अलग संख्या कितनी है और पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके कार्य-निष्पादन का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) सरकार ने उत्पादन हिस्सेदारी संविदा के अधीन तेल और गैस के अन्वेषण के लिए बोली के चौथे दौर में अन्तर्राष्ट्रीय और देशी कम्पनियों को, जिनमें प्रवासी भारतीय भी शामिल हैं, आमंत्रित करने का निर्णय लिया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान अन्वेषण में दो भारतीय कम्पनियां यथा, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इंडिया लिमिटेड और छः अंतर्राष्ट्रीय कम्पनियां लगी हुई थीं। तेल प्राप्त न होने पर पांच अंतर्राष्ट्रीय कम्पनियां वापस हो गई हैं।

ONGC contract for gas exploration

*215. SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE:
SHRI MAHENDRA PRASAD:

Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether Oil and Natural Gas Commission has awarded the ambitious Rs. 16 crores project for exploration of gas in Changer Talai area in Hamirpur district to M|s. Mahindra and Mahindra; and

(b) if so, what are the terms of the contract?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI B. SHANKARANAND): (a) and (b) Not a contract for exploration but a drilling contract has been awarded to Mahindra and Mahindra for Jwalamukhi Project or any other location in Northern Regional Business Centre of ONGC. The contract is on daily rate basis for a period of two years for one rig.

Coal supply to consumers

*216. SHRI SOM PAL:
SHRI CHIMANBHAI MEHTA:

Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether it is a fact that materialisation of rail programme of the coal supply to consumers is very much short of the allotments if so, what is the materialisation of the allotment of coal through rail programme in Western Coalfields during the last three years;

(b) whether it is fact that recently Western Coalfields have decided that 40 per cent of rail programme of the consumers can be issued for road release against consumers rail shortfall; if so, the manner in which the remaining unfulfilled quota will be disposed of;